	State/Union Territories	1971 Workers	1981 Workers	1991 Main Workers	1991 Marginal Workers	1991 Total Workers
26	Dadra & Nagar Haveli	3,102	3,615	2,677	1,739	4,416
27	Delhi	17,120	25,717	26,670	681	27,351
28	Daman and Diu	7,391	9,378	741	200	941
29	Goa			3,938	718	4,656
30	Lakshadweep	97	56	17	17	34
31	Mizoram	***	6,314	6,391	10,020	16,411
32	Pondicherry	3,725	3,606	2,565	115	2,680
	Total	10,753,985	13,640,870	9,082,141	2,203,208	11,285,349

* Includes figures of Mizo district also which then formed part of Assam.
** Census could not be conducted.
*** Census figures of 1971 in respect of Mizoram included under Assam.
NB: Figures for 1991 relates to workers of age group 5-14 years.

Exploitation of house hold workers

2815. DR. GOPALRAO VITHALRAO PATIL: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the exploitation of part time or full time workers, mainly house-maids, young children, working in private house holds; and

(b) whether Government propose to launch any scheme to ameliorate the suffering of these maids and children?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) Attention of the Government has been drawn to the plight of domestic servants including house-maids and young children. In all such cases reports have been obtained from the State Governments who have stated that such workers are not attached to any specific households but work on payment basis in a number of house-holds. These workers have irregular timings and unspecified terms relating to leave. Apart from wages they are getting other benefits like clothes, meals, accommodation etc.

(b) At present there is no proposal to launch any welfare scheme for these workers.

Registration of Unemployed Persons

2816. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that registration of unemployed persons has increased over the last three years; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) Yes, Sir.

(b) The number of job seekers, all of whom need not necessarily be unemployed, who registered themselves in the Employment Exchanges during the year 1995, 1996 and 1997 were of the order of 58.6, 58.7 and 63.2 lakh respectively.

श्रम न्यायालयों में विवादों का निपटान

2817. श्रीमती मालती शर्मा:
श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के श्रम न्यायालयों में कर्मचारियों के विवादों का शीघ्र निपटान करने के

संबंध में लापरवाही बरती जा रही है जिसके परिणामस्वरूप प्रभावित कर्मचारियों को भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है; और

(ख) क्या सरकार श्रम न्यायालयों में विवादों के शीघ्र निपटान के लिये कुछ दिशा निर्देश जारी करने का विचार रखती है जिससे कि कर्मचारियों का न्यायालयों में विश्वास बना रह सके?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) यह सच नहीं है कि दिल्ली में श्रम न्यायालयों में कर्मचारियों के विवादों के अविलम्ब निपटान में लापरवाही है। इस समय दिल्ली में तीन औद्योगिक न्यायाधिकरण और दस श्रम न्यायालय कार्य कर रहे हैं। इन न्यायालयों का संचालन दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इस समय सभी पद भरे हुए हैं।

(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1948 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में श्रम न्यायालयों/औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा औद्योगिक विवादों के निपटान के लिए समय-सीमा की व्यवस्था है।

असंगठित श्रमिकों का कल्याण

2818. **श्री नागमणि:**
चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों के कल्याण और विकास के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कर्मकारों के अधिकारों की रक्षा करने और उनके कल्याण के लिए संगठित और असंगठित दोनों तरह के कर्मकारों के लिए अनेक श्रम कानून अधिनियमित किए गए हैं। इनमें से कुछ कानून हैं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, उपदान संदाय अधिनियम, 1972, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970, बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966, अंतर-राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 आदि। लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और माइका खानों, सिने उद्योग और बीड़ी उद्योग में लगे हुए कर्मकार भी संबंधित कल्याण निधियों के अधीन चलाए जा रहे विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत शामिल हैं। राज्य सरकारों ने भी बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई हैं जिसके दायरे में हथकरघा बुनकरों, रिक्शा चालकों जैसे विशिष्ट कार्यकलापों में लगे एक बड़ी संख्या में कर्मकारों को रखा गया है। असंगठित कर्मकारों के नियोजन की गुणवत्ता और सेवा शर्तों में सुधार किया जाना सरकार के लिए सदैव ही चिन्ता का विषय रहा है

जहां तक नये नीतिगत कार्यकलापों का संबंध है, केन्द्रीय सरकार ने निर्माण उद्योग, जो कि कृषि के बाद द्वितीय सर्वाधिक बड़ा एकल कार्यकलाप है और जिसमें असंगठित क्षेत्र के कर्मकार नियोजित हैं, में नियोजित कर्मकारों के हितों की रक्षा करने के लिए भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 का अधिनियमन किया है। सरकार का यह भी प्रयास रहा है कि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिक से अधिक कर्मकारों को विद्यमान उपायों में बढ़ोतरी की जाए और कल्याण उपायों को प्रदान किया जाए और विधायी संरक्षण प्रदान किया जाए।

भविष्य निधि संगठनों द्वारा निवेश

2819. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठनों द्वारा निवेश के संबंध में प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं के उल्लंघन से संबंधित मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) क्या विभागेतर कर्मचारियों द्वारा वित्तीय गबन और धोखाधड़ी के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस संबंध में अब तक कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले है; और

(ङ) गुजरात, उडीसा और मध्य प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध क्या